



राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड
प्रेस नोट

देहरादून 23 मार्च, 2011

राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने आज राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विचार-विमर्श किया तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।

राजभवन के सभागृह में आहूत बैठक में राज्यपाल द्वारा, जुलाई 2010 की बैठक में आये प्रमुख प्रकरणों के संदर्भ में कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त करने के साथ ही विश्वविद्यालयों के साथ विभिन्न कालेजों के सम्बद्धीकरण, विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढीकरण, रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती, शिक्षकों तथा कुलपतियों के वेतन में वृद्धि, उनकी आयु सीमा तथा सेवा शर्तों सम्बन्धी एक्ट में परिवर्तन आदि पर भी चर्चा हुई। लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राज्यपाल ने निर्देशित किया कि पूर्व में गठित तीन सदस्यीय समिति, जिसमें उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, शासन से आवश्यक समन्वयन स्थापित करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के समस्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु निरन्तर अनुश्रवण करेंगे।

राज्यपाल/कुलाधिपति ने असम्बद्ध कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की कठिनाई को देखते हुए कालेजों के सम्बद्धीकरण विषय पर शासन के प्रतिनिधियों व कुलपतियों से विस्तृत विचार विमर्श करते हुए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिये कि सम्बद्धता के लिए यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संबद्धीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाये किन्तु यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब न हो। इसी क्रम में संस्कृत कालेजों की स्थिति को भी एक सप्ताह के अन्तर्गत स्पष्ट करने के निर्देश कुलपति को दिये गये।

विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व संरचनात्मक विकास के साथ ही भावी लक्ष्यों (Future Focus) पर चर्चा के दौरान राज्यपाल ने कहा:- "राज्य व देश के विकास के लिए पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाया जाना नितांत आवश्यक है। आतिथ्य सत्कार, हॉस्पिटल मैनेजमेंट तथा जलागम केन्द्रित विषय, नर्सिंग ट्रेनिंग जैसे पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता पर शामिल किया जाये क्योंकि इनकी मांग राज्य सहित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है।" उन्होंने विश्वविद्यालयों में खेल/क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियाँ बढ़ाये जाने पर भी बल दिया।

राज्यपाल ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सैल (रोजगार स्थापन प्रकोष्ठ) को सक्रिय करने तथा अप्रैन्टिसशिप स्कीम को अपनाने के प्रयास करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने परीक्षा तथा परीक्षाफल की प्रक्रिया को प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक वर्ष जून माह तक पूर्ण करने के लिए सभी कुलपतियों को निर्देशित किया कि इसके लिए समय-सारिणी भी निर्धारित की जाये।

बैठक में सचिव राज्यपाल श्री अशोक पर्ई, प्रमुख सचिव आयुष श्री राजीव गुप्ता, प्र.स. उच्च शिक्षा श्री पी.सी.शर्मा, प्र0स0 तकनीकी शिक्षा श्री राकेश शर्मा, सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर सचिव राज्यपाल श्री अरुण ढौड़ियाल, एडीसी मेजर चौधरी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

-----0-----